सिफ्सा
SIFPSA

IN NEWS

Publication: Hindustan Times	Date: 26 Jun 2018
Edition: Lucknow	Page: 03

HINDUSTAN TIMES, LUCKNOW
TUESDAY, JUNE 26, 2018

hindustantim

FP initiative in state to get a fillip

MOU SIGNED SIFPSA, JSK ink pact to enhance pvt sector role, with extra incentive and increased target

HT Correspondent
lkoreportersdesk@htlive.com

LUCKNOW : Uttar Pradesh got a booster dose on Monday to promote family planning in the private sector.

The state has 81 lakh couples with unmet family planning needs.

"Doctors from the private sector performing family planning procedures will now get an extra ₹1,100 over the routine ₹3,000 per case, which is a major incentive in the past several decades," said Rajesh Bangia, deputy GM, projects, in State Innovations in Family Planning Services Project Agency (SIFPSA).

An MoU to this effect was signed between Jansankhya Sthirta Kosh (JSK) or National Population Stabilisation Fund and SIFPSA for the Hausla Sajhedari project that runs the family planning initiative.

In the past three years; out of the total 2.65 lakh family planning procedures, 55,000 were done by private sector hospitals/doctors. With extra monetary benefit, the target for the private sector this year has been raised to one lakh.

Under the MoU, there is provision that in case of a legal suit by the beneficiaries against empanelled hospitals/doctors, the Hausla Sajhedari initiative will support the doctors legally.

Minister for family welfare, women and child development UP Rita Bahuguna Joshi launching the 'Hausala Sajhedari' initiative in Lucknow on Monday. SUBHANKAR CHAKRABORTY/HT PHOTO

> Doctors from the private sector performing family planning procedures will now get an extra ₹1,100 over the routine ₹3,000 per case.
> RAJESH BANGIA, deputy GM, projects, in SIFPSA

There are 1,000 hospitals in the state and over 750 doctors empanelled for Hausla Sajhedari project. There are 106 doctors and 67 hospitals in Lucknow.

"The private sector has been improving its performance over the years. If you compare the outcome you can see that the number of cases has increased and we hope the MoU will further raise the figures," said Bangia.

Since 2015, private sector's contribution to family planning procedures has been on the rise. In 2015, 21,735 female sterilisations were done in the private sector. In 2016, the number rose to 45,964 and in 2017 to 54,829.

IN 2018 (till June), 3,193 sterilisations have been done. Also the number of private hospitals empanelled for family planning procedures rose from zero in June 2015 rose to 1042 in June 2018 and the number of private surgeons from zero in June 2015 to 774 in June 2018.

"We hope more surgeons will join the task to bring down the fertility rate," said Bangia.

At present, 57 districts in the state have total fertility rate (TFR) of over 3, which means a woman bearing three or more children in a lifetime. "Two will be an ideal situation," said Bangia. Managing director, National Health Mission (NHM) Pankaj Kumar in his address said that about 81 lakh couples had unmet needs out of which 38 lakh wished to opt for permanent methods.

'POPULATION KEY FACTOR IN PROGRESS'

LUCKNOW: Women welfare minister Rita Bahuguna Joshi said that population was a key factor in the progress of the nation.

She said that in developing countries, lack of education and information and poverty were the main contributors to population instability, i.e. both excess and low population.

She said that though many doctors had joined family planning programmes, still there was need of doctors in rural areas.

MOBILE UNITS

LUCKNOW: Apart from the empanelled hospitals and doctors, there are 18 mobile units too. These units have private sector doctors who use the government establishments/operating theatre in community health centres or hospitals to conduct family planning procedures. They visit places where there is lack of doctors for conducting procedures. These doctors are also paid incentives for each case.

IN NUMBERS

32%
couples in Uttar Pradesh use modern family planning methods

81 lakh
couples wish to use them but have unmet needs

1,042
private hospitals and 774 doctors are associated with Hausla Sajhedari project

1,25,721
female sterilisation performed since 2015

सिफ्सा
SIFPSA

IN NEWS

Publication: Hindustan **Date: 26 Jun 2018**

Edition: Lucknow **Page: 08**

नसबंदी करने वाले डॉक्टरों का 11 सौ रुपये बढ़ा

परिवार कल्याण

लखनऊ | वरिष्ठ संवाददाता

जनसंख्या पर काबू पाने के लिए केंद्रीय परिवार कल्याण विभाग ने अहम कदम उठाया है। प्राइवेट क्षेत्र के डॉक्टरों को जोड़ा जा रहा है।

नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टरों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उनके मानदेय में भी 11 सौ रुपये प्रति केस के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है। अभी तीन हजार रुपये प्रदान किए जा रहे थे। यह व्यवस्था सिर्फ प्राइवेट क्षेत्र के डॉक्टरों पर लागू होगी। यह जानकारी स्टेट इनोवेशन इन फैमली प्लानिंग सर्विस प्रोजेक्ट एजेंसी (सिप्सा) में डिप्टी जनरल मैनेजर राजेश बांगिया ने दी।

पीपीपी मॉडल पर परिवार नियोजन कार्यक्रम : एनएचएम, जनसंख्या स्थिरता कोष, सिप्सा और पीएसआई के सहयोग से गोमतीनगर के एक होटल में परिवार नियोजन पर कार्यशाला हुई। डिप्टी जनरल मैनेजर राजेश बांगिया ने कहा कि नसबंदी कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

पोर्टल बनाया गया है। इसमें डॉक्टरों को जोड़ा गया है। इससे नसबंदी कराने वालों और डॉक्टरों को भुगतान में आसानी हुई है। बढ़ी हुई रकम तभी डॉक्टर को मिलेगी जब वह माह में 10 से अधिक नसबंदी के ऑपरेशन करेंगे।

57 जिलों में प्रति परिवार तीन से ज्यादा बच्चे : राजेश बांगिया ने कहा कि यूपी के जनसंख्या के लिहाज से 57 जिले अहम हैं। इनमें प्रत्येक परिवार में तीन से ज्यादा बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार अधिक बच्चों वाले जिलों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

अब तक 776 डॉक्टरों को जोड़ा जा चुका है। वहीं सरकारी क्षेत्र के 1027 डॉक्टर नसबंदी कर रहे हैं।

बढ़ा नसबंदी का ग्राफ : उदय कुमार ने बताया कि सरकारी क्षेत्र में करीब 2 लाख 15 हजार महिला व पुरुष नसबंदी हो रही है।

प्राइवेट क्षेत्र में 50 हजार से ज्यादा नसबंदी हुई हैं। वहीं बीते वर्षों में यह आंकड़ा दो लाख से भी कम था। उन्होंने बताया कि 17 जिलों में एम्बुलेंस क्लीनिक का संचालन किया जा रहा है।

सराहनीय कदम

- जनसंख्या पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने उठाए कदम
- अभी 3000 रुपये प्रदान किए जा रहे थे प्रत्येक ऑपरेशन के लिए
- सरकारी क्षेत्र के 1027 डॉक्टर नसबंदी के क्षेत्र में काम कर रहे

32 % दम्पति ही अपना रहे परिवार नियोजन के साधन

परिवार कल्याण विभाग की महानिदेशक डॉ. नीना गुप्ता ने कहा कि 32 प्रतिशत दम्पति परिवार नियोजन के आधुनिक साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं परिवार कल्याण विभाग की मंत्री डॉ. रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि तरक्की के लिए परिवार नियोजन जरूरी है। क्योंकि सभी चीजे सीमित हैं लेकिन उपभोग करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से सभी तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। यदि जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार यही रही तो मुश्किलें बढ़नी तय हैं। पीपीपी मॉडल पर परिवार नियोजन की सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने का फैसला मील का पत्थर साबित होगा। शहर से लेकर गांव तक व्यवस्था दुरुस्त होगी।

Hindustan - 26 June 2018 (Pg no. 8)

सिफ्सा
SIFPSA

IN NEWS

Publication: Dainik Jagran **Date: 26 Jun 2018**

Edition: Lucknow **Page: 06**

6 दैनिक जागरण लखनऊ, 26 जून 2018 लखनऊ जागरण

अब निजी अस्पताल में नसबंदी पर ज्यादा इनाम

जासं, लखनऊ : जनसंख्या नियंत्रण के लिए नसबंदी कार्यक्रम में तेजी लाई जाएगी। महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों की भी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। इसके लिए निजी क्षेत्रों के सहयोग से कार्यक्रम का दायरा बढ़ाया जाएगा। सोमवार को टॉप-अप अमाउंट योजना लॉन्च कर इसकी शुरुआत की गई। इसमें निजी अस्पतालों में नसबंदी होने पर प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया गया।

यूपी में परिवार नियोजन सेवाओं के लिए राज्य सरकार, एनएचएम व सिफ्सा के साथ-साथ अब केंद्र सरकार के जनसंख्या स्थिरता कोष को भी जोड़ दिया गया है। महिला एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. रीता बहुगुणा जोशी ने गोमती नगर स्थित एक होटल में 'जनसंख्या

हौसला साझेदारी कार्यक्रम जनसंख्या स्थिरता कोष से जुड़ा मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि पुरुषों की बढ़ाएं भागीदारी

स्थिरता कोष टॉप-अप योजना' लॉन्च की। इसमें हौसला साझेदारी कार्यक्रम से जुड़े अस्पताल व उसके लाभार्थियों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का फैसला किया गया। इस दौरान मंत्री ने परिवार नियोजन कार्यक्रम में महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों की भी भागीदारी बढ़ाने को कहा है। कार्यक्रम में निदेशक एनएचएम पंकज कुमार, डीजी परिवार कल्याण डॉ. नीना गुप्ता समेत तमाम चिकित्सक मौजूद रहे।

निजी क्षेत्र में नसबंदी का ग्राफ 16 फीसद पहुंचा : स्टेट नोडल ऑफीसर राजेश बांगिया ने कहा कि हौसला साझेदारी योजना सितंबर 2015 में शुरू हुई थी। इसमें अब 1027 निजी अस्पताल संबंद्ध हैं। वहीं लखनऊ के 67 अस्पताल शामिल हैं। साथ ही 776 सर्जन और 17 मोबाइल वैन हैं। स्थिति यह है कि शुरुआत में निजी क्षेत्र में नसबंदी सिर्फ एक फीसद होती थी, वहीं बढ़कर अब 16 फीसद हो गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्षभर में दो लाख 65 हजार के करीब नसबंदी होती है। वहीं हौसला साझेदारी कार्यक्रम के तहत वर्ष 2015 में 21,735, वर्ष 2016 में 45,964, वर्ष 2017 में 54,829 नसबंदी हुई। इसके अलावा वर्ष 2018 में अब तक 3200 नसबंदी हो चुकी हैं। इसमें पुरुष नसबंदी 4,486 है।

चिकित्सकों की सरकार करेगी मदद : स्टेट नोडल ऑफीसर के मुताबिक योजना से संबंद्ध निजी सर्जन को कोई दिक्कत होने पर सरकार उनकी कानूनी मदद करेगी। ऐसे में चिकित्सकों को बेवजह परेशान नहीं होना पड़ेगा।

महिला को 1600, पुरुष को 2100

हौसला साझीदारी कार्यक्रम के स्टेट नोडल ऑफीसर राजेश बांगिया ने कहा कि राज्य में नॉन एमपीवी व एमपीवी जिले चुने गए हैं। एमपीवी जनपद वो हैं जिनमें टोटल फर्टीलिटी रेट (टीएफआर) तीन से अधिक है। यानी कि एक व्यक्ति के तीन से अधिक बच्चे हैं। ऐसे यूपी के 57 जिले हैं। इन जिलों में नसबंदी का पैकेज 3500 से बढ़ाकर 4600 कर दिया गया है। वहीं नॉन एमपीवी जिले में नसबंदी का पैकेज बढ़ाकर 3000 रुपये से 4100 कर दिया गया। इसी पैकेज से अब महिला नसबंदी का एक हजार से बढ़ाकर 1600 व पुरुष नसबंदी का एक हजार से 2100 रुपये कर दिया गया। यह पैकेज अस्पतालों को दस नसबंदी के बाद ही मिलेगा।

सिफ्सा
SIFPSA

IN NEWS

Publication: Amar Ujala | **Date: 26 Jun 2018**

Edition: Lucknow | **Page: 06**

निजी डॉक्टरों को प्रति नसबंदी अब 1100 रुपये अधिक मिलेंगे

अब तक प्रति ऑपरेशन पर मिलते थे 3000, अब 4100 रुपये मिलेंगे, जनसंख्या नियंत्रण के लिए केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्रालय ने उठाया कदम

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्रालय ने नसबंदी करने वाले निजी डॉक्टरों की प्रोत्साहन राशि में 1100 रुपये की बढ़ोतरी की है। उन्हें प्रति नसबंदी ऑपरेशन 3000 रुपये की जगह अब 4100 रुपये मिलेंगे। डॉक्टरों को यह बढ़ी हुई रकम एक महीने में दस से ज्यादा ऑपरेशन करने पर ही मिलेगी। अभी तक उन्हें प्रति केस तीन हजार रुपये मिलते थे।

यह जानकारी स्टेट इनोवेशन इन फैमिली प्लानिंग सर्विस प्रोजेक्ट एजेंसी (सिफ्सा) के डिप्टी जनरल मैनेजर राजेश बागिया ने सोमवार को एक होटल में परिवार नियोजन पर हुई कार्यशाला के दौरान दी। उन्होंने बताया कि पीपीपी मॉडल से परिवार नियोजन की सुविधाओं को लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है।

एनएचएम (जनसंख्या स्थिरता कोष), सिफ्सा व पीएसआई के सहयोग से हुई कार्यशाला में राजेश बागिया ने बताया कि नसबंदी कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए पोर्टल बनाकर डॉक्टरों को जोड़ा गया है। इससे नसबंदी कराने और डॉक्टरों का भुगतान करने में आसानी हुई है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश की जनसंख्या में 57 जिले बेहद अहम हैं। इनमें प्रति परिवार में तीन से ज्यादा बच्चे हैं। यह जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों को बढ़ाने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। इस बार इन जिलों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इसे कंट्रोल में करने के लिए निजी डॉक्टरों को योजना से जोड़ा गया है। इसके तहत अब तक 776 निजी व 1027 सरकारी डॉक्टर नसबंदी कर रहे हैं।

हौसला साझेदारी के बाद से बढ़ा नसबंदी का ग्राफ

2015 से शुरू हुए हौसला साझेदारी कार्यक्रम से लोगों में संजीदगी बढ़ी है। सरकारी क्षेत्र में करीब 2 लाख 15 हजार महिला व पुरुषों की नसबंदी हो रही है जबकि निजी क्षेत्र में 50 हजार से ज्यादा हुई हैं। बीते वर्षों में यह आंकड़ा दो लाख से भी कम था। 17 जिलों में एम्बुलेंस क्लीनिक चलाई जा रही हैं।

32% दंपती ही अपना रहे परिवार नियोजन के साधन

परिवार कल्याण विभाग की महानिदेशक डॉ. नीना गुप्ता ने बताया कि 32% दंपती परिवार नियोजन के आधुनिक साधन प्रयोग कर रहे हैं। वहीं 81% इसकी विधियों व इनमें से 38% स्थाई विधि का प्रयोग करना चाहते हैं।

जनसंख्या नियंत्रण जरूरी : जोशी

परिवार कल्याण विभाग की मंत्री डॉ. रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि तरक्की और जिंदगी के बेहतर स्तर के लिए परिवार नियोजन जरूरी है। यदि जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार यही रही तो मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। पीपीपी मॉडल पर परिवार नियोजन की सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने में काफी आसानी होगी।